साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 41 | प्रति सोमवार इंदौर, 13 से 19 मई 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

शेर का बच्चा इस चुनाव में मेमना क्यों बन रहा

56 इंच की दहाड़ क्यों बदली घबराहट में

विश्व का पहला चुनाव जिसमें सत्ताधीश विपक्ष के घोषणा पत्र की कर रहे व्याख्या

कैसे घबराया साहिब, बात-बात पर डरता है!

शुक्रवार, 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान ने, संघ-भाजपा की कुशंकाओं की और बाकी सब के इसके व्यापक अनुमानों की पुष्टि कर दी है कि जिस मोदी लहर का इतना ढोल पीटा जा रहा था, वह तो खैर इस चुनाव में खोजने से भी नहीं मिलेगी, अलबत्ता इस बार मोदी उतार के काफी प्रबल लक्षण हैं। ये लक्षण, 4 जून को मोदी के सत्ता से उतरने तक ले जाएंगे या उससे कुछ पीछे रह जाएंगे या पहले ही रोक दिए जाएंगे, इसके लिए तो बेशक अभी सवा महीने और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन, इस चुनाव में मोदी के उतार पर रहने के जो लक्षण पहले चरण में सामने आये थे, उनकी दूसरे चरण ने पुष्टि कर दी है। पहले चरण में अगर, 2019 के चुनाव के मुकाबले, 102 सीटों पर हुए मतदान में कुल मिलाकर 4 फीसद वोट की गिरावट देखने को मिली थी, तो दूसरे चरण के मतदान में भी वही रुझान बना रहा है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर जो वोट पड़े हैं, उनमें 2019 के चुनाव के मुकाबले 3 फीसद से अधिक गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट से पहले चरण के बाद से लगाए जा रहे इस अनुमान की पुष्टि हो गयी है कि मतदान में यह गिरावट, कमो-बेश इस पूरे चुनाव की ही विशेषता रहने जा रही है। जाहिर है कि इस गिरावट के संकेत भी, पूरे चुनाव के लिए ही सच होने चाहिए।

दूसरे चरण की 88 सीटों में इस गिरावट में बेशक, केरल में हुई 6.5% की गिरावट भी शामिल है। लेकिन, इस राज्य की 20 सीटों पर मुकाबले से भाजपा को तो एक तरह से बाहर ही माना जा रहा है और इसलिए इसके रुझान से भाजपा की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पर इस चरण में मत फीसद में यह गिरावट 13 राज्यों में से पूरे 11 में दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ही इसका अपवाद रहे हैं और कम से कम कर्नाटक का इस रुझान का अपवाद रहना तो, किसी भी तरह से भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। कुछ ही महीने पहले जोरदार तरीके से कांग्रेस के शासन में आये कर्नाटक में, जहां 2019 में भाजपा 28 में से 26 सीटों पर काबिज हो गयी थी, मत फीसद में बढ़ोतरी उसके संसदीय बोलबाले के छीजने का ही संकेत हो सकती है।

बहरहाल, भाजपा के लिए इससे भी महत्वपूर्ण संकेत, उसका गढ़ मानी जाने वाली हिंदी पट्टी में मत फीसद में बिहार में 3.5 फीसद, मध्य प्रदेश में 9.1 फीसद, उत्तर प्रदेश में 7 फीसद, राजस्थान में 3.4 फीसद की गिरावट होना है। पहले चरण में भी दर्ज हुई इस गिरावट का दूसरे चरण में भी जारी रहना, इसका स्पष्ट संकेत है कि 2019 के चुनाव में, सबसे बढ़कर पुलवामा और बालाकोट के सहारे, राष्ट्रवाद के जिस आख्यान के बल पर उठाई गई लहर के ज्वार ने भाजपा को तीन सौ पार पहुंचाया था, वह ज्वार कब का उतर कर भाटा बन चुका है और इस बार पूरे चुनाव में भाटा ही बना रहने जा रहा है। यह वही हिंदी पट्टी है, जहां विपक्ष के नाम पर कांग्रेस को मप्र तथा बिहार में एक-एक सीट और उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा का एका होने के बाद भी, उसे 15 तथा कांग्रेस को एक सीट ही मिल पाई थी। उसी हिंदी पट्टी में मतदान में उल्लेखनीय गिरावट, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के प्रति मतदाताओं की उदासीनता से लेकर विमुखता तक का खुला ऐलान कर रही है।

जैसा कि अधिकांश राजनीतिक प्रेक्षकों ने दर्ज किया, पहले चरण के मतदान के संकेतों से हुई घबराहट का नतीजा, खुद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के अपनी प्रचार कार्यनीति में साफ-साफ दिखाई देने वाला बदलाव कर, खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक अपील को प्रचार केंद्र में लाने के रूप में सामने आया। हिंदी भाषी पट्टी में ही राजस्थान में, बांसवाड़ा के अपने कुख्यात भाषण से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की, जिसमें कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र तथा उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह के 2006 के एक भाषण का नाम लेकर, विपक्ष पर गरीब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की संपत्तियों, विशेष रूप से महिलाओं का सोना तथा मंगलसूत्र तक जब्त करने के मंसूबे बनाने का ही आरोप नहीं लगाया गया, नाम लेकर यह आरोप भी लगाया गया कि वे ये संपत्तियां छीनकर मुसलमानों में यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में, घुसपैठियों में बांटेगी! (शेष पेज 7 पर)

भारत में अवैध लोन ऐप्स की काली दुनिया

12 अगस्त को, मध्य भारतीय शहर भोपाल में एक परिवार ने अपने घर में एक सेल्फी ली। फोटो के बाद पिता भूपेन्द्र विश्वकर्मा ने अपने आठ और तीन साल के दो बेटों को जहरीला पेय पदार्थ पिला दिया और खुद तथा उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

एक बीमा कंपनी में काम करने वाले 35 वर्षीय विश्वकर्मा ने अपने चार पेज के सुसाइड नोट में लिखा है कि वह लोन ऐप्स से कर्ज के चक्र में फंस गए थे। रिकवरी एजेंट उसे महीनों से परेशान कर रहे थे और उनसे मिले आखिरी संदेश ने उसे किनारे कर दिया था।

इसमें कहा गया, 'उसे कर्ज चुकाने के लिए कहो; नहीं तो आज उसे नंगा करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा।'

अपने सुसाइड नोट में, विश्वकर्मा ने कहा, 'आज स्थिति मेरी नौकरी खोने तक पहुंच गई है। मैं अपने और अपने परिवार के लिए भविष्य नहीं देख सकता। अब मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही। मैं अपने परिवार का सामना कैसे करूंगा?' पुलिस ने जांच जारी रखते हुए अब तक घोटाले में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

(शेष पेज 2 पर)

कुल वोटिंग के 20% नोटा में तो रद्द हो पूरा चुनाव

जनता को रिजेक्ट ही नहीं रिकॉल का मिले अधिकार

पुन: चुनाव में पुराना कोई उम्मीदवार न हो। हर दल नये उम्मीदवार खड़े करें

इंदौर में वाचाल भ्रष्ट देश को बर्बाद करने वाले अपने कुकर्मों भ्रष्टाचारों डकैतियों देश को बर्बाद करने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर नाच देश को बेचने बेरोजगार करने भूख से मारने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर जगह भारत की छवि को बर्बाद करने बेरोजगारी में 129वें नंबर पर भुखमरी में 123वें नंबर पर, प्रति व्यक्ति आय में 143वें क्रम की उपलब्धियों से, 10 साल भर से ज्यादा समय से चल रहा है। फिर जनता को अनावश्यक रूप से थोपी गई सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी कोरोना व जबरदस्ती ठोंक गये मौत के टीके की आड़ में 15 करोड़ लोगों की मौत का तांडव और उसके बाद प्रधानमंत्री का यह कहना कि जनसंख्या नियंत्रण में आ रही है। स्पष्ट करता है कि सारा खेल जो प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी ने 10 साल में सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी का खेला यू टॉटम अमेरिकी 1 वर्ल्ड आर्डर का देश की जनसंख्या को बेरोजगारी भुखमरी फर्जी बीमारी और टीके से जनता की मौतों के तांडव कर खत्म करने के षड्यंत्र का हिस्सा थी। फिर खनिजों से भरी मणिपुर की धरती को पूंजी पतियों के लिए कब्जे में लेने के लिए चलाये जा रहे जातिवादी आंदोलन जिसमें मैतेई और कुकी समाज में आपस में हिंसात्मक तांडव करवा महिलाओं को पुलिस के सामने और संरक्षण में नग्न कर घुमाया गया। (शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

अब जब सिद्ध हो चुका है टीका मौत का कारण

मोदी-कलेक्टर्स समाचार पत्रों-टीवी चैनलों के खिलाफ दर्ज करो मुकदमा

जनता कीड़े मकोड़े नहीं जो उसकी मौत से खेलते रहे 10 साल। अंतरराष्ट्रीय स्तरपर टीका बनाने वाली कंपनियांकी का सच जब सामने आ चुका है तो अब जबरदस्ती टीका ठोकने के लिए उन समाचार पत्रों की कॉपियां जिन में हवाई, रेल, बस यात्रा, सभी मंदिरों यथा महाकाल ऊंकारेश्वर, खजराना आदि मंदिरों, शिक्षा संस्थानों, बाजारों, मंडियों में प्रवेश करने के लिए टीका लगाना आवश्यक है। की प्रतियां निकालिए और उन जिलों के कलेक्टरों, नगर निगमों, पालिकाओं पंचायतों के आयुक्तों मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ समाचार पत्रों पर भी केस ठोक दीजिए।

जिनके सदस्यों को 24 घंटे समाचार पत्रों मोबाइलों टीवी समाचार चैनलों पर दहशत फैलाकर जबरदस्ती टीका ठोकने से मौत हो गई।

सारी जनता बाहर निकलो दस्तावेजों को जिसमें टीके के प्रमाण पत्र पर मोदी की फोटो लगी है। इकट्ठे करो और न्यायालय पहुंचो। अगर सत्ता और पूंजीपतियों के पक्ष में नियम कानून को त्याग कर फैसला दे।

तो न्यायाधीशों को भी घेरो। उन्हे सरकार नहीं जनता के धन से जनहित में न्यायालयों में विश्वास बनाने बनाए रखने नियम कानून का पालन कर निष्पक्ष न्याय देने के लिए वेतन मिलता है।

ना की पूंजीपतियों और सत्ताधीशों के पक्ष में नियम कानूनों को तोड़ मरोड़ कर जन जंगल जमीन जलवायु जानवरों की वर्तमान भविष्य की पीढ़ीयों को बर्बाद व नष्ट करने उनके पक्ष में फैसला देकर न्यायालयों के प्रति जनता का विश्वास तोड़ने के लिए बेशक सौ डेढ़ सौ साल पुराने बनाए गए कानूनों में समय व जन, जानवर जंगल जमीन जल वायु के के भविष्य के लिए श्रेष्ठ हितों को ध्यान में रख कानूनी व्याख्या में फिर बदल किया जा सकता है पर किसी खास के फायदे के लिए करोड़ों लोगों प्राकृतिक पशु पक्षियों वनों जल वायु का वर्तमान भविष्य हितों को कुचला व बर्बाद नहीं किया जा सकता।

भारत में अवैध लोन ऐप्स की काली दुनिया

पेज 1 का शेष

विश्वकर्मा की कहानी अनोखी नहीं है. दिल्ली में एक 23 वर्षीय कॉलेज रिसेप्शनिस्ट शिवानी रावत को अपनी खुद की परीक्षा का सामना करना पड़ा। जून 2023 में, उन्होंने 'क्रेडिटबे' नामक ऐप के माध्यम से 4,000 रुपये ($48) के ऋण के लिए आवेदन किया, क्योंकि उनके वेतन में देरी हो रही थी। उसका ऋण अनुरोध लंबित रहा, कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। फिर भी, एक सप्ताह के भीतर, उसे पुनर्भुगतान के लिए 9,000 रुपये ($108) की मांग करते हुए 10-15 कॉल आने लगीं। रावत ने कहा कि उन्होंने रिकवरी एजेंटों को बताया कि उनके खाते में कोई पैसा नहीं आया है, लेकिन उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब मैंने उनकी कॉल का जवाब देना बंद कर दिया, तो उन्होंने मुझे अपमानजनक संदेश भेजना शुरू कर दिया। अगस्त में, उनके सहकर्मियों को उनकी और उनके परिवार की हेरफेर की गई स्पष्ट तस्वीरें मिलीं जो क्रेडिटबे के प्रतिनिधियों द्वारा भेजी गई थीं। उसने अपने सहकर्मियों को स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन, उसके प्रबंधक ने उसे इस्तीफा देने के लिए कहा क्योंकि उसकी उपस्थिति से अन्य लोग असहज हो गए थे।

रावत ने स्वीकार किया, "नौकरी खोने के बाद मैं इतना उदास हो गया कि मेरे मन में अपनी जिंदगी खत्म करने तक के ख्याल आने लगे।"

अल जज़ीरा ने टिप्पणी के लिए क्रेडिटबे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फर्म पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी और रावत के संपर्क में रहने वाला कोई भी प्रतिनिधि अब उपलब्ध नहीं था। क्रेडिटबे का नाम क्रेडिटबी नामक एक वैध ऋण ऐप का धोखा है, जो इन अवैध ऋण ऐप्स के लिए एक सामान्य कार्यप्रणाली है जो प्रामाणिकता की भावना पैदा करने के लिए अक्सर प्रतिष्ठित ब्रांडों के समान नाम चुनते हैं।

विश्वकर्मा और रावत दोनों ने ऋण देने वाले ऐप्स से पैसा उधार लिया था, जो उपयोगकर्ताओं को सुविधाजनक, कुछ ही क्लिक में और पारंपरिक बैंक ऋण के लिए आवश्यक व्यापक दस्तावेजों के बिना ऋण प्रदान करते हैं। उच्च पात्रता सीमा को पूरा करने वाले उधारकर्ताओं के लिए बैंक ऋण में लगने वाले पांच से सात दिनों के विपरीत, पैसा कुछ ही मिनटों में उधारकर्ता के खाते में जमा कर दिया जाता है।

महामारी के दौरान इन ऐप्स के उपयोग में वृद्धि देखी गई क्योंकि कई व्यवसाय बंद हो गए या कम हो गए, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और वित्तीय कठिनाइयों में पड़ गए।

इन ऐप्स में औसत ऋण टिकट 10,000 रुपये से 25,000 रुपये ($120 से $300) के बीच है, जिसमें मासिक ब्याज दर 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत और प्रसंस्करण शुल्क 15 प्रतिशत तक हो सकता है।

ऋण ऐप प्रतिनिधि आम तौर पर ऋण स्वीकृत करने के 15 दिन बाद वसूली प्रक्रिया शुरू करते हैं। हालाँकि, कई मामलों में, वे ऋण वितरित करने के चार से छह दिन बाद ही लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, और तिवारी के मामले में, यह वास्तव में ऋण प्राप्त करने से भी पहले था।

भोपाल में एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अक्षय बाजपेयी के अनुसार, वर्तमान में, देश में 700 से अधिक लोन ऐप चल रहे हैं, जिनमें से कुछ भारतीय हैं लेकिन अधिकांश चीनी स्वामित्व वाले हैं और उन्हें चलाने के लिए भारतीयों को नियुक्त करते हैं।

जबकि उनमें से कुछ पूरी तरह से धोखेबाज हैं और रात में गायब होने से पहले हताश ऋण चाहने वालों से शुल्क प्राप्त करने के लिए त्वरित धन का वादा करते हैं, अन्य लोग न केवल उन दुर्भावनापूर्ण तरीकों के कारण अस्पष्ट क्षेत्र में हैं, जो वे निर्दोष लोगों से पैसे ऐंठने के लिए अपनाते हैं, बल्कि क्योंकि वे वार्षिक ब्याज दर, विभिन्न शुल्कों सहित ऑनलाइन ऋण देने पर केंद्रीय बैंक के नियमों का पालन नहीं करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी ऋण देने वाली संस्था ग्राहक का नाम, पता और संपर्क विवरण जैसे कुछ न्यूनतम डेटा को छोड़कर ग्राहक विवरण संग्रहीत नहीं कर सकती है। हालाँकि, अवैध ऐप्स संपर्क सूचियों और चित्रों तक पहुँचते हैं, उन्हें संपादित करते हैं और पैसे वसूलने के लिए उधारकर्ताओं को ब्लैकमेल करने के लिए हेरफेर की गई छवियों का उपयोग करते हैं।

साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर कंपनी क्लाउडसेक द्वारा 22 जुलाई, 2023 से 18 सितंबर, 2023 के बीच किए गए एक अध्ययन के अनुसार, उनके विशेषज्ञों ने व्यक्तियों को लक्षित करने वाले 55 धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स की निगरानी की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने चीनी मूल के व्यक्तियों द्वारा संचालित 15 से अधिक अस्पष्ट भुगतान गेटवे की पहचान की, जिन्होंने पहचान से बचने के लिए ये कदम उठाए।

चीनी ऋण ऐप्स दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ अफ्रीकी देशों में भी इस कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं। उन देशों में जहां लोग साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी के बारे में कम जागरूक हैं, लोग ऐसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं।

डर पैदा करना

लोन ऐप्स के प्रतिनिधि शिवानी रावत को प्राप्त धमकी भरे और अपमानजनक संदेशों और कॉलों से उधारकर्ताओं को परेशान करते हैं डसौजन्य शिवानी रावत

'घोटालेबाज विभिन्न हथकंडे अपनाकर अपने पीड़ितों के मन में डर पैदा करते हैं। प्रारंभ में, वे पीड़ित की संपर्क सूची तक पहुंचने और कॉल करने की धमकी दे सकते हैं। यदि पीड़ित विरोध करता है, तो वे पीड़ित की फोटो गैलरी में घुसपैठ कर सकते हैं, छवियों में हेरफेर कर सकते हैं और उन्हें वापस भेज सकते हैं, 'साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने वाले एक गैर सरकारी संगठन, सेवेम इंडिया के संस्थापक प्रवीण कलाईसेल्वन ने बताया।

उन्होंने आगे कहा, 'इससे पीड़ितों में घबराहट पैदा होती है और अंततः उन्हें घोटालेबाजों की पैसों की मांग पूरी करनी पड़ती है।' पिछले तीन वर्षों में, लोन कंज्यूमर एसोसिएशन (एलसीए), जो कि बैंकों और ऐप्स द्वारा अनैतिक वसूली प्रथाओं का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह है, ने इन अवैध ऋण ऐप जाल में फंसे लगभग 1,800 लोगों को परामर्श और उन्हें फाइल करने में मदद की है। पुलिस से शिकायत,

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एलसीए के संस्थापक निखिल जेटवा के अनुसार, इनमें से लगभग 90 प्रतिशत व्यक्ति नैदानिक अवसाद और संकट से जूझ रहे थे। उन्होंने याद करते हुए कहा कि जब उनके फोन की घंटी बजती थी तो कुछ लोग घबरा जाते थे या कांपने लगते थे।

बढ़ती शिकायतें

सेव देम इंडिया फाउंडेशन के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2020 में देश में कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में लॉकडाउन लगाने के बाद से डिजिटल ऋण देने की शिकायतें बढ़ गई हैं।

उस वर्ष, फाउंडेशन को ऋण ऐप्स के प्रतिनिधियों से डराने-धमकाने वाले कॉल और संदेशों की डरावनी कहानियों से भरी लगभग 29,000 शिकायतें मिलीं। 2021 में यह संख्या लगभग 76,000 हो गई। इस साल के पहले नौ महीनों में उन्हें 46,359 शिकायतें मिली हैं।

लोकल सर्कल द्वारा जुलाई 2020 से जून 2022 तक किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 14 प्रतिशत भारतीयों ने पिछले दो वर्षों में तत्काल ऋण आवेदनों का उपयोग किया। अट्ठाईस प्रतिशत को 25 प्रतिशत की अत्यधिक ब्याज दरों का सामना करना पड़ा और 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संग्रह प्रक्रिया के दौरान जबरन वसूली या डेटा दुरुपयोग की घटनाओं का अनुभव किया।

'सरकारी एजेंसियां तैयार नहीं'

अपने सुसाइड नोट में, विश्वकर्मा ने लिखा कि वह भोपाल में साइबर अपराध कार्यालय का दौरा किया, लेकिन अधिकारियों से कोई सहायता नहीं मिली। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है, उन्होंने अल जज़ीरा को बताया कि पुलिस को साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

'साइबर-पुलिस स्टेशनों में कई पुलिसकर्मियों के पास बुनियादी इंटरनेट ज्ञान भी नहीं है, जबकि साइबर अपराधी नवीनतम तकनीक से सुसज्जित हैं। यही कारण है कि अधिकांश साइबर अपराध अनसुलझे रह जाते हैं,'' उन्होंने कहा।

भारतीय पुलिस साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं है डफाइल: अजीत सोलंकी/एपी फोटो

इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस स्कैमर्स द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अन्य उपकरण है क्योंकि जो कंपनियां यह सेवा प्रदान करती हैं व इसे सख्त दस्तावेज के बिना प्रदान करती हैं। कलैसेल्वन ने कहा, इसका उपयोग उन लोगों को लक्षित करने के लिए किया जाता है जो फेसबुक जैसी साइटों पर ऑनलाइन सक्रिय नहीं हैं, जहां ऋण ऐप्स आमतौर पर अपने ऐप्स का विज्ञापन करते हैं।

इनमें से अधिकांश घोटालेबाज बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के वर्चुअल नंबरों का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

कलैसेल्वन ने कहा, 'ऋण घोटालेबाज इन सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है।' विशेषज्ञों के अनुसार, इन ऐप्स में आम तौर पर ऐसे नाम होते हैं जिनमें 'आसान', 'लोन', 'आधार' और 'ईएमआई' जैसे कीवर्ड शामिल होते हैं, जिससे उन्हें ऑनलाइन खोजों के माध्यम से आसानी से खोजा जा सकता है (आधार 12 अंकों की अद्वितीय आईडी है जिसकी भारत में लोगों को आवश्यकता है) बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए)।

इसके अतिरिक्त, वे अपनी सेवाओं को फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों और उद्धृत पर इसके ऐडों के माध्यम से प्रचारित करते हैं जो वेबसाइट मालिकों को अपने उपयोगकर्ता आधार का विस्तार करने के लिए लक्षित विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। जब इन ऐप्स को प्रतिबंध या शिकायतों का सामना करना पड़ता है, तो वे अक्सर अपने नाम और अन्य विवरण बदल देते हैं, एक नई पहचान के साथ फिर से उभर आते हैं।

जेटवा ने कहा, लोन ऐप घोटालेबाज बैंक खातों के माध्यम से पैसे निकालते हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड की उपलब्धता के बावजूद, बहुत कम घोटालेबाज पकड़े जाते हैं। एक कारण यह है कि बहुत कम भारतीय डिजिटल रूप से समझदार हैं। ऑक्सफैम की भारत असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, देश में केवल 38 प्रतिशत परिवारों के पास डिजिटल साक्षरता है। जेटवा ने कहा, 'सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देती है, लेकिन हमारे पास लोगों के लिए बुनियादी ढांचे और साइबर-साक्षरता कार्यक्रमों की कमी है।

उपाय किए मार्च में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी ऋण ऐप्स द्वारा किए गए वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में बेंगलुरु में 1.06 बिलियन रुपये (₹ 12.76 मिलियन) की चल संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने कहा कि इन कंपनियों ने ऋण ऐप्स और अन्य चैनलों के माध्यम से जनता को तेजी से अल्पकालिक ऋण की पेशकश की, अत्यधिक उच्च ब्याज दरों के साथ भारी प्रसंस्करण शुल्क लगाया। उन्होंने लगातार फ़ोन धमकियाँ देने और भावनात्मक संकट पैदा करने सहित, ज़ोरदार रणनीति के माध्यम से उधारकर्ताओं से रकम वसूल की। एक रिपोर्ट में, उद्धृत ब्लूँ ने कहा कि उसने अपनी नीतियों और विनियमों का पालन करने में विफलता के कारण 2022 में अपने ऐप स्टोर से 3,500 से अधिक व्यक्तिगत ऋण आवेदन हटा दिए। ये ऐप्स गैरकानूनी तरीके से कॉन्टैक्ट्स और फोटो समेत यूजर डेटा तक पहुंच बना रहे थे। सितंबर 2022 में, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि RBI कानूनी ऐप्स की एक सूची बनाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये स्वीकृत ऐप्स उद्धृत Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध हों। 7 फरवरी, 2023 को एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने Google Play Store और Apple App Store जैसे ऐप स्टोरों को स्वीकृत डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की एक श्वेतसूची भेज दी है। हालाँकि, उस बयान को स्थानीय मीडिया ने खारिज कर दिया था जिसमें बताया गया था कि ऐसी कोई सूची नहीं भेजी गई थी। लगभग उसी समय, केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स केंद्रीय बैंक के नियामक दायरे में नहीं हैं। उसी महीने सरकार ने 94 ऋण देने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें बडीलोन, कैशटीएम, इंडियाबुल्स होम लोन, पेमी, फ्लाइसेट और रुपीरेडी जैसे नाम शामिल थे। इन ऐप्स को आरबीआई द्वारा विभिन्न कारणों से चिह्नित किया गया था, और इनमें से कई में या तो चीनी निवेशक थे या उधारकर्ताओं को परेशान करने में शामिल थे। इनमें से कुछ ऐप्स, जिनमें रुपीरेडी भी शामिल है, ने कहा है कि वे स्कैमर्स द्वारा प्रतिरूपित किए जा रहे थे।

मप्र आबकारी विभाग में चारों तरफ जालसाजी, भ्रष्टाचार का तांडव

सूचना के अधिकार में जानकारी देने में जिलों से मुख्यालय तक जालसाजी

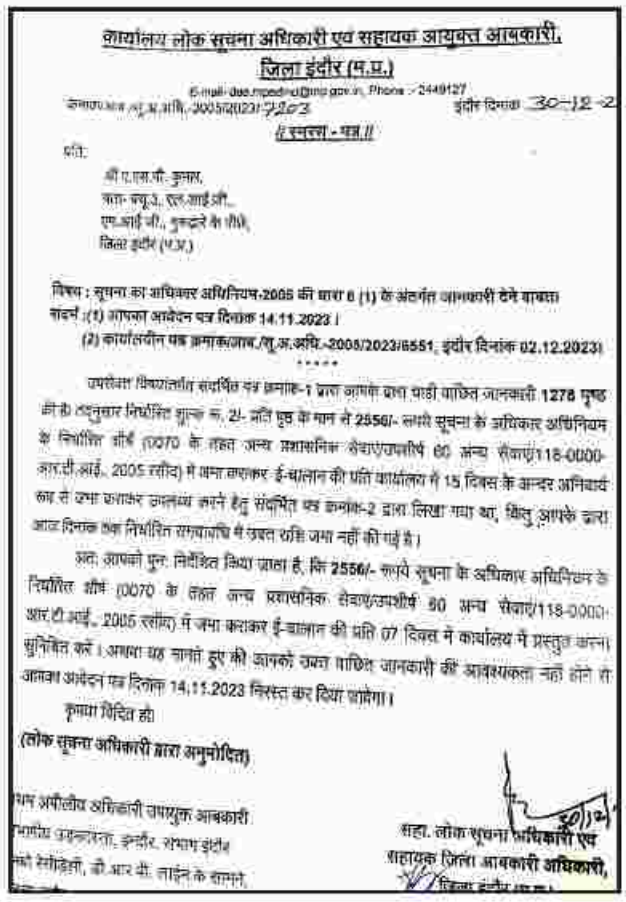

मध्य प्रदेश शासन की राजस्व आय का महत्वपूर्ण हिस्सा आबकारी विभाग की देसी विदेशी मदिरा, भांग गांजा अफीम आदि की बिक्री के ठेकों की नीलामी के साथ उत्पादन प्रसंस्करण बोतलों की भराई आदि से होती है। दूसरी तरफ उत्पादन पर आबकारी करारोपण के बाद बिक्री पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्भ सुनने के कारण मध्य प्रदेश के उत्पादित देसी विदेशी मदिरा पर सबसे ज्यादा कर वसूला जाता है। इसके बाद में भी बड़ी मुश्किल से सालों लिखाने के बाद शराब की बोतलों पर प्रदेश में उत्पादित बिक्री के लिए शराब की बोतलों पर उसकी कीमत लिखना शुरू की गई इसके विपरीत बिक्री करने वाला ठेकेदार उस पर अपनी मोटी कमाई के लिए 10-20 से रु.100 ज्यादा तक प्रति बोतल पर वसूलता है और लिखी हुई कीमत के बारे में बात करने पर या खरीदी पर बिल मांगने पर दुकान पर बैठे ठेकेदार के कर्मचारी ग्राहकों को पहले चलता करने की कोशिश करते हैं और बिल मांगने पर अभी बिल छपे नहीं हैं, बिल बनाने वाला कर्मचारी नहीं है।

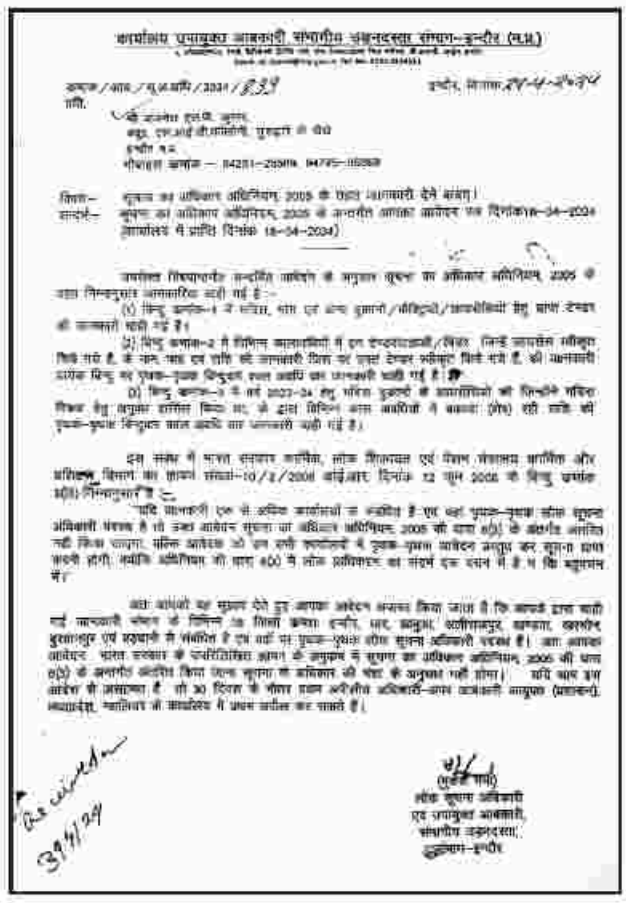

बिल कट्टा अकाउंटेंट के पास पड़ा हुआ है। फिर भी ग्राहक अगर बिल की हठ पर अड़ जाए तो बदतमीजी दिखाकर अपमान करने से लेकर लड़ने मारने तक पर उतारू हो जाते हैं। परंतु ग्राहक को शराब खरीदी का बिल नहीं देते। यह बिल्ला देने की कर प्रणाली इंदौर की दुकानों से लेकर प्रदेश की सभी दुकानों की है जो बिल नहीं देते और प्रति बोतल प्रिंटेड रेट और लिखी हुई दर सूची से ज्यादा पर टिकाते हैं। पूछने पर मुख्यमंत्री का, बड़े साहब का आयुक्त का आदेश है, को भेजना पड़ता है। कहकर टालने धमकाने की कोशिश की जाती है जिसकी शिकायत अनेको बार अनेको मदिरा प्रेमियों ने थाने से लेकरहर स्तर पर की परंतु निराशा ही हाथ लगी।

इन सब षड़यंत्रों के पीछे यथार्थ में जिला के सहायक आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारियों के साथ पूरे विभाग के निरीक्षकों और विक्रेता के संबंधित थाने का पूरा गिरोह कार्य करता है। जिनको शराब उत्पादक व विक्रेता दुकानदार महीना बांटते हैं। स्वाभाविक सी बात है जब आबकारी पुलिस के निरीक्षक से लेकर बीटगार्ड तक संबंधित उत्पादकों विक्रेताओं से ही महीना खाएंगे तो उन्हें कर चोरी अधिक वसूली की छूट के साथ-साथ क्रेताओं से मोटी अवैध वसूली को भी पालने पोसने और मारपीट वसूली की शिकायत आने पर उनको बचाने के लिए ना या तो रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे आदम चेक काट कर दे देंगया उसे शिकायत के आधार पर पुनः समझौता करवा कर मामले को रफा दफा करने की भी मोटी वसूली कर लेते हैं।

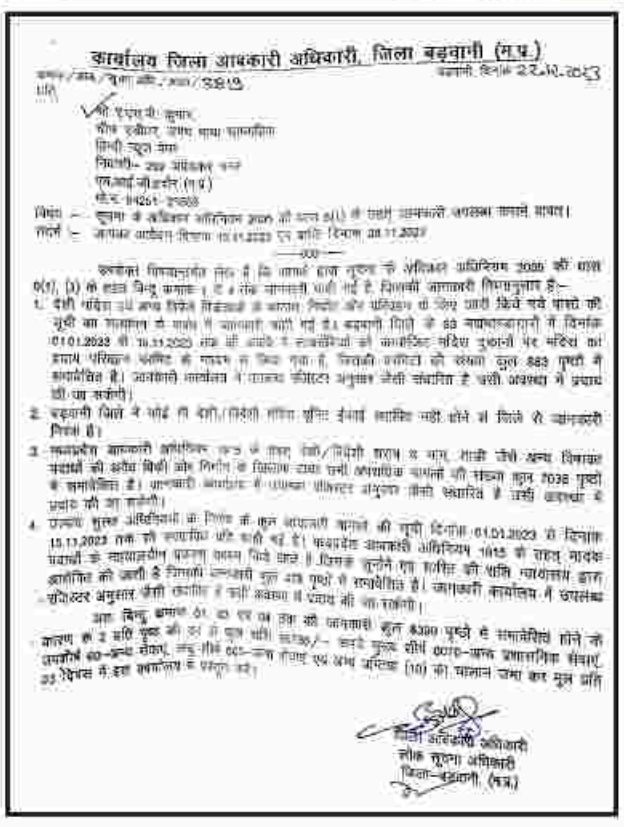

वैसे भी आबकारी जो वित्त मंत्री के राजस्व आय प्रधान सचिव से लेकर जिसके अंतर्गत आयुक्त आबकारी, महा निरीक्षक मुद्रांक व पंजीयन, आयुक्त वाणिज्य कर तीनों मलाईदार विभाग आते हैं और तीनों में ही शासकीय राजस्व की वसूली में भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। मध्य प्रदेश में 2324 में इंदौर में आबकारी से 1501.71 करोड़ की आय हुई जो मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर थी दूसरे नंबर पर भोपाल जिसकी आय 1040.02 करोड़ हुई तीसरे नंबर पर जबलपुर जिसने 748.73 करोड़ रुपए की आय हुई। पर यथार्थ में जितनी आय हुई। उससे दुगनी लूट घोर भ्रष्ट जालसाज आबकारी आयुक्त से लेकर जिलों के सहायक आयुक्त व जिला अधिकारियों निरीक्षकों ने उससे आधी कमाई करके शासन के राजस्व की नानी की और यही कारण है कि यह हरामखोर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लगे हुए 19 साल गुजर जाने के बाद अभी तक धारा 4 के 25 बिंदुओं की जानकारी अपनी आबकारी की साइट पर उपलब्ध नहीं करवा पाए ताकि यह पर्याप्त चारों तरफ भ्रष्टाचार से कमाई करते हुए अवैध तरीके से शराब का उत्पादन परिवहन विक्रय में मोटी कमाई कर सके दूसरी तरफ प्रदेश के अधिकांश ठेको में वही संभागीय जिला आबकारी कार्यालयों के उपयुक्त सहायक आयुक्त जिला अधिकारियों निरीक्षकों से लेकर बीट गार्ड तक की हिस्सेदारी तो कही महीना वसूली का खेल और राजस्व की हानि पहुंचा कर अनवरत चलता रहता है। यही कारण है की घोर भ्रष्ट आबकारी विभाग में चपरासी से लेकर कार्यालयो में बैठे बाबू निरीक्षकों बीट गार्ड सिपाही जिलाधिकारी सहायक आयुक्त तक सारे भ्रष्ट किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते और सब भ्रष्टाचार की आठ मेआवेदक को देखने के बाद दाएं बाएं मुंह बिचकाते नजर आते हैं।

बेशक उनके ग्राहक जो कि ठेकेदार होते हैं। हमको महीना बनते हैं उनको या उनके कर्मचारियों को देखकर जरूर उनके चारों तरफ दुम हिलाते नजर आते हैं। क्योंकि उनसे कमाई की उम्मीद रहती है। जबकि सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वाले उनको शत्रु दिखाई पड़ते हैं।

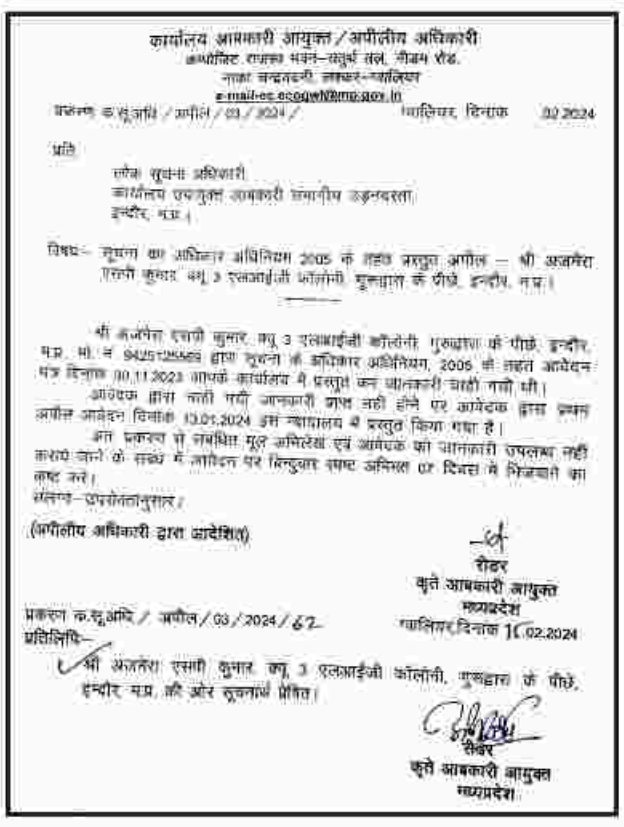

आवेदन लेने में भी भारी परेशान किया जाता है। जानकारी मांगी जाती है तो छोटी-छोटी सी जानकारी के भी हजारो रुपए के बिल दिए जाते हैं। जबकि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2(j)iv के अंतर्गत स्पष्ट है कि जो कार्य कंप्यूटर पर किया जाता है और जो सामग्री रिकॉर्ड दस्तावेज कंप्यूटर में संचित है। उन्हें आपको उसी रूप में कंप्यूटर से सीडी में देना है। परंतु सीडी देने के नाम पर हर कार्यालय में यही बहाना बनाया जाता है तो सिडी ड्राइवर राइटर नहीं है हमारे यहां इसलिए जानकारी देना संभव है जबकि अपने बाप को जब मुख्यालय में पहुंचाते हैं। तो सीडी और पेन ड्राइव लेकर जाते है।

आवेदन में मैं यूआरएल और सीडी मांगता हूं। जिसकी व्यवस्था 2005 में लगे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(j)iv के अंतर्गत स्पष्ट ढंग से की गई है के बाद में भी सीडी देने की अपेक्षा मात्र परेशान करने जानकारी न देने और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यह हरामखोर मोटी चमड़ी के सूकरों की फौज जिला कार्यालयों से लेकर आबकारी के मुख्यालय ग्वालियर तक केवल टालने के अलावा कुछ नहीं देते। जबकि मध्य प्रदेश सरकार सन 2010 से यह लगातार घोषणा कर रही है कि उसका सारा सरकारी कार्यालय में जो काम है वह कागज विहीन कंप्यूटर पर होता है। यह हाल मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में से 12 जिलों में सूचना के अधिकार मांगने पर किया जा रहा है।

बेशक कुछ छोटे जिले चाही गई जानकारी को न्यूनतम लागत में उपलब्ध करवा देते हैं। जिलो की अपील संभागीय कार्यालय में होती है परंतु संभागीय कार्यालय अधिकांश समय बिना बुलाए बिना सुने एक तरफा फैसला लेकर सारी अपील है रद्द कर देते हैं क्योंकि उन सबके भी संभागीय कार्यालय के संभागीय उपायुक्त को व वहां बैठे अधिकारियों को महीना मिलता है। इसलिए उनको बताना जानकारी छुपाना यथार्थ में लूट भ्रष्टाचार छुपाना, व राजस्व को हानि पहुंचाना ही है। इसके लिए ही सूचना अधिकार कानून बनाया गया है। यह खेल इंदौर संभाग के इंदौर धार झाबुआ खंडवा खरगोन बुरहानपुर बड़वानी के साथ उज्जैन संभाग के उज्जैन देवास शाजापुर मंदसौर नीमच रतलाम आगर मालवा सब जगह चल रहा है। सूचना के अधिकार में लगाए गए आवेदन के जवाब अपीलों के उत्तर की बिना बुलाए या बिना वीडियो कॉलिंग पर सुने एक तरफ जवाब की मुख्यालय की कॉपियां यहां प्रस्तुत हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के 25 बिंदुओं की स्पष्ट व पूरी जानकारी 19 साल बाद भी उपलब्ध नहीं

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)

इंदौर दिनांक 30-12-2

// स्मरण - पत्र //

प्रति:
श्री ए.एस.पी. कुमार,
जिला इंदौर (म.प्र.)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत जानकारी देने बाबत।
संदर्भ :(1) आपका आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2023।
(2) कार्यालयीन पत्र क्रमांक/आब./सू.अ.अधि.-2005/2023/6551, इंदौर दिनांक 02.12.2023।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा आपके द्वारा चाही गई वांछित जानकारी 1278 पृष्ठ की है तदनुसार निर्धारित शुल्क रु. 2/- प्रति पृष्ठ के मान से 2556/- रुपये सूचना के अधिकार अधिनियम के निर्धारित शीर्ष (0070 के तहत अन्य प्रशासनिक सेवाएं/उपशीर्ष 60 अन्य सेवाएं/118-0000-आर.टी.आई., 2005 रसीद) में जमा कराकर ई-चालान की प्रति कार्यालय में 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर उपलब्ध कराने हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक-2 द्वारा लिखा गया था, किंतु आपके द्वारा आज दिनांक तक निर्धारित समयावधि में उक्त राशि जमा नहीं की गई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है, कि 2556/- रुपये सूचना के अधिकार अधिनियम के निर्धारित शीर्ष (0070 के तहत अन्य प्रशासनिक सेवाएं/उपशीर्ष 60 अन्य सेवाएं/118-0000-आर.टी.आई., 2005 रसीद) में जमा कराकर ई-चालान की प्रति 07 दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा यह मानते हुए की आपको उक्त वांछित जानकारी की आवश्यकता नहीं होने से आपका आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2023 निरस्त कर दिया जावेगा।

कृपया विदित हो।

(लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त आबकारी

सहा. लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)

कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग-इन्दौर (म.प्र.)

इन्दौर, दिनांक 29-4-2024

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी देने बाबत।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मुख्यालय-इन्दौर

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला बड़वानी (म.प्र.)

बड़वानी, दिनांक 22.12.2023

जिला आबकारी अधिकारी
लोक सूचना अधिकारी
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

कार्यालय आबकारी आयुक्त / अपीलीय अधिकारी

ग्वालियर, दिनांक 02.2024

प्रति
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता
इन्दौर, म.प्र.।

(अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेशित)

कृते आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र.सू.अधि./अपील/03/2024/62
ग्वालियर दिनांक 16.02.2024

कृते आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

साप्ताहिक समय माया

L

सिंदूर लगाने से महिलाओं को हो सकता है ब्रेन कैंसर

हिंदू समाज में शादीशुदा महिलाओं के लिए सिंदूर का बहुत महत्व होता है। सिंदूर न सिर्फ महिलाओं के सुहागन होने की निशानी होती है बल्कि इसके बिना कोई भी शादीशुदा महिला का श्रृंगार अधूरा ही होता है। लेकिन क्या आपको पता हैं बाजार में मिलने वाले सिंदूर से आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। कुछ स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि मार्केट में मिलने वाले सिंदूर को लगाने से महिलाओं को ब्रेन कैंसर का खतरा भी हो सकता है। बाजार में जो सिंदूर मिलता है उसमें कई तरह के केमिकल मिले होते हैं जो महिलाओं के बालों को सफेद करने के साथ ही उनके झड़ने का कारण भी बनता है। बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक सिंदूर को लगाने से प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चों पर भी इसका गलत असर हो सकता है।

मार्केट में मिलने वाले सिंदूर में हानिकारक रसायन जैसे पाउडर क्रूड लीड, आर्टिफिशियल डाई, अन्य सिंथेटिक डाई, पारा सल्फाइट और रोडियामाइन बी डाई मौजूद होता है जो आपकी स्किन के साथ आपके हेल्थ पर भी इसका नेगेटिव इंपेक्ट पड़ता है। ऐसे में आप मार्केट में मिलने वाले सिंदूर को लगाने से बचें। तो आइए जानते हैं आप घर पर ही अपना हर्बल सिंदूर कैसे तैयार कर सकते हैं। हर्बल सिंदूर बनाने की रेसिपी

सिंदूर बनाने के लिए सामग्री

-हल्दी पाउडर

-नींबू का रस

पानी सिंदूर बनाने की विधि -घर में सिंदूर बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 2 से 3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर ले लें। आप चाहे तो हल्दी की गांठों से घर में ही अपना हल्दी पाउडर तैयार कर सकते हैं।

-अब अपने हल्दी पाउडर में कुछ बूंदे नीबू के रस की डालें और इसे अच्छी तरह मिला लें।

-नींबू का रस हल्दी पाउडर के लाल रंग को उभरकर बाहर आने में मदद करेगा। -अब इसका पेस्ट बनाने के लिए इस मिश्रण में पानी की कुछ बूंदें डाल कर एक पेस्ट तैयार कर लें।

-ध्यान रहें आपके सिंदूर का पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए। बहुत हल्का या बिल्कुल सूखा नहीं।

-अब इस पेस्ट को एक साफ, सूखी सतह पर फैलाएं और इसे धूप में या पंखे के नीचे सूखने दें।

-जब आपके सिंदूर का पेस्ट पूरी तरह सूख जाएं तो इसे मिक्सर जार में डालकर पाउडर बना कर छलनी की मदद से छान लें।

-आपका सिंदूर तैयार है, इसे किसी डिब्बी में स्टोर करके रख लें। ●

सुपारी है कई बीमारियों के लिए राम बाण

सुपारी का नामक सुनते ही ज्यादातर लोगों को गुटखा व तंबाकू याद आता है, जबकि ये एक काष्ठफल है। इस फल में फ्लेवोनोइड, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, आइसोप्रेनाइड, एमिनो एसिड और यूजेनॉल जैसे खास तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर के लिए कुछ जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं और कई बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं। लेकिन, गर्मियों में, सुपारी के सेवन के खास फायदे हैं क्योंकि ये इस मौसम में होने वाली कई बीमारियों से बचा सकती है। आइये जानते हैं।

मुंह में छाले होने पर

मुंह में छाले होने पर सुपारी का सेवन कई प्रकार से फायदेमंद है। दरअसल, सुपारी का पानी पीने से पेट में बढ़ा हुआ एसिडिक पीएच कम होता है। साथ ही ये बढ़े हुए पित्त को कंट्रोल करने में भी मदद करता है जिससे मुंह में होने वाले छाले में कमी आती है।

बवासीर में

बवासीर में सुपारी का पानी पीना कई प्रकार से फायदेमंद हो सकता है। ये बॉवेल मूवमेंट और मेटाबोलिज्म तेज करने में मददगार है। साथ ही ये कब्ज की समस्या को कम करने में मददगार है। इस तरह ये बवासीर की समस्या में मल त्याग और मल मार्ग में सूजन की समस्या को कम करने में मददगार है। ●

गठिया की बीमारी

गठिया की बीमारी में भी सुपारी का सेवन कई प्रकार से फायदेमंद है। ये दर्द निवारक की तरह काम करता है और गठिया के दर्द को कम करने में मदद करता है। साथ ही ये शरीर में टॉक्सिन को कम करता है और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मददगार है।

पेशाब में जलन होने पर

सुपारी की तासीर ठंडी होती है और दूसरा ये डाययूरेटिक की तरह काम करती है। ऐसे में पहले तो ये जलन को शांत करती है और पेशाब की मात्रा बढ़ा देती है। इससे पेशाब में जलन की समस्या कम होती है और यूटीआई की दिक्कत में भी आप आराम महसूस करते हैं।

आपकी लापरवाही के चलते कमजोर हो सकती हैं आंखें

जब आंखों के हेल्दी रखने की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि समय-समय पर आई टेस्ट (आंखों की जांच) कराना काफी होता है। लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं। जांच के साथ ही अच्छा खानपान, स्क्रीन

टाइम कम करना जैसी चीजें भी आंखों को हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर आप चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए जानते आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए किन आदतों को अपनाना है जरूरी।

आंखों को स्वस्थ रखने वाली आदतें-

आंखों को धूप से बचाएं

सूरज की अल्ट्रावायोलेट किरणें हमारी त्वचा को ही नहीं बल्कि आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए, जब धूप होती है या जब आप बहुत अधिक चकाचौंध वाली जगह पर होते हैं, जैसे कि बर्फ या पानी के पास, धूप का चश्मा (सनग्लासेस) पहनें। 100 प्रतिशत यूवी (UV) संरक्षण वाले ऐसे धूप के चश्मे में (सनग्लासेस) अपने बैग में जरूर रखें।

हेल्दी डाइट लें

आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए डाइट में ओमेगा -3 फैटी एसिड, जिंक, विटामिन सी और ई रिच फूड्स को शामिल करें। इसके अलावा हरी सब्जियां, सैल्मन फिश, अंडे, साबुत अनाज, चिकन और खट्टे फलों में भी आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

कान्टैक्ट लेंस

अगर आप कान्टैक्ट लेंसेस पहनते हैं, तो उनकी अच्छी देखभाल करना जरूरी है. इंफेक्शन के खतरे को कम करने के लिए, अपने कान्टैक्ट लेंसेस डालने या हटाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोएं। कभी भी अपने लेंस पहनकर न नहाएं, न सोएं और न ही स्वीमिंग क्योंकि इससे इंफेक्शन के साथ ही आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा हो सकता है। ●

नहीं पड़ेगी डॉक्टर और दवाइयों की जरूरत, अगर आज से ही अपना लेंगे ये 5 आदतें

खानपान और लाइफस्टाइल की खराब आदतें आज ऐसी-ऐसी बीमारियों की वजह बन रही है जिन्हें ठीक करने के लिए डॉक्टर और दवाइयों के लिए अच्छे-खासे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कई बीमारियों को तो इतने पैसे खर्च करने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता बस कंट्रोल में ही रखा जा सकता है, जैसे- डायबिटीज़, मोटापा और बीपी। तो अगर आप डॉक्टर की महंगी फीस और दवाइयों में अब और ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो यहां दिए जा रहे हेल्थ टिप्स को आज से भी शुरू कर दें फॉलो करना।

1. **धूप सेंकें**
2. **रोजाना वर्कआउट करें**
3. **हेल्दी डाइट लें**
4. **भरपूर मात्रा में पानी पीएं**
5. **6-8 घंटे की नींद लें**

मां बगलामुखी को कैसे करें खुश..?

10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या बगलामुखी है। बगलामुखी देवी का प्रकाट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्रकाट्य हुआ था। इसी कारण माता को पीतांबरा कहते हैं। मुकदमे आदि में इनका अनुष्ठान सफलता प्राप्त करने वाला माना जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को विजय प्राप्त होती है। शुत्र पूरी तरह पराजित हो जाते हैं।

क्या अर्थ है बगलामुखी का?

बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। कुब्जिका तंत्र के अनुसार, बगला नाम तीन अक्षरों से निर्मित है व, ग, ला; व अक्षर वारुणी, ग अक्षर सिद्धिदा तथा ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। अतः मां के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त है।

बगलामुखी माता का वार कौन सा है?

माता का वार शुक्रवार माना जाता है, कुछ विद्वान गुरुवार को पूजा का विधान बताते हैं। उनकी तिथि अष्टमी है।

वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। बगलामुखी जयंती को मां बगलामुखी प्रकटोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 15 मई 2024 को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी।

मां को कैसे खुश करें?

- हल्दी या पीले कांच की माला से आठ माला ऊँ ह्रीं बगुलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः दूसरा मंत्र- ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। मंत्र का जाप कर सकते हैं।
- देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप-दान करें, देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है, बगलामुखी देवी के मन्त्रों से दुखों का नाश होता है। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे।

प्राचीन तंत्र ग्रंथों में दस महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। 1. काली 2. तारा 3. षोड़षी 4. भुवनेश्वरी 5. छिन्नमस्ता 6. त्रिपुर भैरवी 7. धूमावती 8. बगलामुखी 9. मातंगी 10. कमला। मां भगवती श्री बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है।

15 मई को मां बगलामुखी प्रकटोत्सव के दिन शुभ मुहूर्त में करें देवी की आराधना

हर साल वैशाख मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से देवी बगलामुखी की आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं होती है।

सनातन धर्म में देवी बगलामुखी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो भी भक्त सच्चे मन से मां बगलामुखी की आराधना करता है, उसके जीवन में आ रही सभी परेशानियां देवी हर लेती हैं। इसके अलावा देवी की पूजा खासतौर पर कोर्ट-कचहरी और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए की जाती है।

चलिए अब जानते हैं हर साल बगलामुखी जयंती कब मनाई जाती है? इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि माता रानी को किन-किन चीजों का भोग लगाना शुभ होता है?

मां बगलामुखी की पूजा का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। बगलामुखी जयंती को मां बगलामुखी प्रकटोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 15 मई 2024 को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी।

बगलामुखी जयंती के दिन देवी की पूजा के दो शुभ मुहूर्त हैं। 15 मई को ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ प्रातः काल 04 बजकर 13 मिनट से हो रहा है, जिसका समापन सुबह 05 बजकर 01 मिनट पर होगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ 14 मई 2024 को दोपहर 01 बजकर 05 मिनट से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 15 मई को प्रातः काल 05 बजकर 49 मिनट पर होगा। इन दोनों ही शुभ मुहूर्त में आप मां बगलामुखी की उपासना कर सकते हैं।

मां बगलामुखी को कौन सा रंग अति प्रिय है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां बगलामुखी की पूजा दस महाविद्या के रूप में भी की जाती है। इसी वजह से देश के कई राज्यों में इन्हें बुद्धि की देवी के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग मां बगलामुखी की पूजा पीताम्बरा देवी के रूप में भी करते हैं। मां बगलामुखी के नाम का अर्थ है, जीभ पर कड़ी पकड़ होना और एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सके।

मां बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है। बगलामुखी जयंती के दिन मां को पीले रंग के कपड़े, फूल या मिठाई अर्पित करना शुभ होता है।

साप्ताहिक समय माया

आखिर एक फौजी की आत्मा झूठ के खिलाफ जाग उठी

मोदी के हजारों झूठ और देश की बर्बादी के खिलाफ दर्ज हो मुकदमा?

देहरादून में रहने वाले एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने थाने में आवेदन देकर पीएम मोदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त डंगवाल ने राजपुर थाने में दिए गए आवेदन में कहा है कि राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने ढेर सारे झूठ बोले हैं जिनका तथ्यों से दूर-दूर तक कुछ लेना-देना नहीं है। और यह देश में नफरत और घृणा फैलाने वाला है।

उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल, 2024 को दिए गए इस भाषण में पीएम मोदी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को, जो घुसपैठिया हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, आपका सारा धन दे देना चाहती है और यहां तक कि आपका मंगलसूत्र भी बेच देगी। उन्होंने कहा कि यह न केवल झूठ है बल्कि सांप्रदायिक वैमनस्य भी पैदा करता है। और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 504 के तहत आता है। लिहाजा इन दोनों धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने आगे धाराओं का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि धारा 153 (ए) भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय और ऐसी गतिविधि किसी भी कारण से ऐसे धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच भय या चिंता या असुरक्षा की भावना पैदा करती है या पैदा करने की आशंका है तो उसे दंडित किया जाएगा।

इसी के साथ उन्होंने धारा 504 का भी विस्तार से वर्णन किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझ कर अपमान करना इस धारा के तहत आता है। इस सिलसिले में साक्ष्य के तौर पर उन्होंने यूट्यूब में पीएम मोदी के उस भाषण के अंश को भी दे रखा है जिसमें उन्होंने यह बोला था।

ब्रिगेडियर डंगवाल ने थाने में यह आवेदन 27 अप्रैल, 2024 को ही दे दिया था। इसकी एक प्रति उन्होंने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया है।

दरअसल ब्रिगेडियर डंगवाल मौजूदा दौर के राजनीतिक माहौल से बहुत विक्षुब्ध हैं। और खास कर सत्ता पक्ष की ओर से जिस तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसको लेकर वह बेहद चिंतित हैं। उनकी यह चिंता उनके द्वारा लिखे गए एक लेख में भी देखी जा सकती है। जिसमें शुरुआत में ही उन्होंने लिखा कि 'आज मैं विवशतापूर्ण होकर यह लेख लिख रहा हूं और जो मेरे मन के उद्गार और भावनाओं से प्रेरित होकर शब्दों की माला में पिरोया गया है।

मैं, स्तब्ध हूं कि आज बाईसवीं शताब्दी के भारत में राजनीतिक संवाद का स्तर इतना नीचे गिर गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आप, यदि जनता द्वारा चुने हुए हमारे विधायक और सांसदों की भाषा सुनेंगे तो आपको मलाल होगा कि हमने ऐसी गंभीर भूल की जिसकी वजह से आज हमको अपने निर्णय पर अफसोस करना पड़ रहा है।'

उन्होंने आगे कहा कि कोई कहता है कि गोली मारो सालों को और कोई कहता है कि यह देश रामजादों का है न कि हरामजादों का। ऐसी भाषा हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कारों को शर्मसार करती है और चोट पहुंचाती है।

इस कड़ी में उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि क्या सत्ता इतनी प्रिय और अहम हो गयी है कि उसके लिए देश का प्रधानमंत्री हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए इतनी अपमानजनक सोच और शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं जैसी उन्होंने 21 अप्रैल, 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा में की।

मुस्लिम को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिया कह दिया। इस कड़ी में उन्होंने चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा। उनका कहना था कि आश्चर्य है कि मुख्य चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल कर माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनाव में भाग लेने से क्यों वर्जित नहीं किया? लेकिन इसका खुद ही जवाब देते हुए वह कहते हैं कि लेकिन जब संस्था ही चाटुकारों का जमघट हो तो फिर हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य और हमारे संविधान का अपमान भी है।

ब्रिगेडियर डंगवाल इसको और साफ करते हुए पीएम मोदी पर हमला और तेज कर देते हैं। उन्होंने लिखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने संबोधन में यह भी कहते हैं कि आप इनको इनके कपड़ों से पहचान सकते हैं। क्या तात्पर्य है यह कहने का? बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा और सिर पर टोपी का उपहास करना। आपके पद की गरिमा को शोभा नहीं देता है महोदय। उन्होंने कहा कि आप इन 15 फीसदी देशवासियों के भी प्रधानमंत्री हैं और यह एक नागवार बात है जो आपको गौरवान्वित नहीं अपितु शर्मसार करती है।

और फिर उन्होंने अपनी पीड़ा को दर्ज करते हुए कहा कि मैं एक इंसान, भारत का नागरिक और सशस्त्र सैनिक होने के कारण आपके ऐसे वक्तव्यों से अपने को बहुत पीड़ित और क्षुब्ध महसूस करता हूं। क्या आपकी इंसानियत खत्म हो चुकी है?

उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि मेरे स्कूल के दोस्त और सहपाठी, हमारे गुरुजन, पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी और सैन्य जीवन के कार्यकाल के सहकर्मी और अधिकारी, हमारे माता-पिता के दोस्त, परिवार के मित्र, बच्चों की दाई और खाना बनाने वाले/वाली, पिता के कार्यालय के बाबू और बड़े बाबू/अर्दली/ महावत/ ड्राइवर, हमारा नाई, हमारा दर्जी, हमारा धोबी, हमारा बढ़ई और हमारे जीवन में आने वाले अन्य सज्जन मुस्लिमों को मैं आपके द्वारा इस तरीके से चिन्हित कर और उनके प्रति देशद्रोहपूर्ण बात कहते हुए नहीं सहन कर सकता हूं।

इसके आगे उन्होंने कहा कि खास तौर से जो सशस्त्र सैनिक हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और वह आपके अनुसार 'घुसपैठिया हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं और अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं' बहुत ही अमर्यादित, शर्मनाक और समाज में आपसी बैर और हिंसा को बढ़ावा देने वाली भाषा है।

आखिर में उन्होंने लिखा कि मैं इस लेख को पूरे देशवासियों के साथ साझा कर रहा हूं और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि जो सेवानिवृत्त सशस्त्र सैनिक हैं वह भी इसके पक्ष में अपनी आवाज उठाएं। हम देशप्रेमी हैं और देशभक्त हैं लेकिन अंध भक्त नहीं हैं जो केवल आपके महिमामंडन में अपना जीवन जी रहे हैं। आज मां भारती का मुंह लज्जा से झुक गया है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी सोच रखता है और सार्वजनिक सभा में बोल सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। और मैं केवल सुशासन का कायल हूं। मैं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अंत में उन्होंने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है? वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है?

कुल वोटिंग के 20% नोटा में तो रद्द हो पूरा चुनाव

पेज 1 का शेष

पर मोदी के मुंह से किसी भी भाषण में मणिपुर का व पूंजीपति मित्रों के लिए फैलाई गई महंगाई का म नहीं निकला। जबकि दोनों ही मोदी की नकारात्मक षड्यंत्रकारी कुत्सित राजनीतियों का हिस्सा है।

8 महीने से ज्यादा समय से चल रहे किसानों के आंदोलन और हर कदम अपनी असफलताओं से भयभीत भाजपाई गिरोह द्वारा किये राजनैतिक छल कपट के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी को दबाव अपहरण की राजनीति से नामांकन वापस करवाने ने इंदौर के चुनाव को एक दम नीरस एक तरफा कर दिया। इसके विकल्प में कांग्रेस ने नोटा को वोट देने का आवाहन कर व चुनकर भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बचाने और विश्व को दिखाने का जो काम किया है। सराहनीय है।

सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि वह किसी भी चुनावी याचिका में जिस प्रकार उपरोक्त में से कोई पसंद नहीं नोटा का विकल्प उपलब्ध करवाया है उसी प्रकार हर 6 महीने में सत्ताधीश हर मंत्री नेता की कार्य पद्धति व उन्नति जैसा कि हर विभाग में होता है, की आवश्यक रूप से जानकारी हर विभाग के मंत्री की कार्यालयीन साइट पर उपलब्ध करवाई जाए। और उन्नति संतोषजनक ना पाए जाने पर जनता को अपनी उस प्रत्याशी को वापस बुलाने का अधिकार भी दिया जाये। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में ऑनलाइन सर्वे करवाने पर यदि नकारात्मक रिपोर्ट आती है तो उसे भी हटाने का अधिकार जनता को दिया जाना चाहिए। सत्ता, सत्ताधीश राजनीतिक दलों के बाप की जागीर नहीं है। जो चाहे मन में आए अपने खास लोगों के लिए करते रहो और जनता को मरने के लिए छोड़ दो। जैसा की प्रकृति का नियम है की हर व्यक्ति को दूसरों से नहीं अपने ही कुकर्मों से ज्यादा डर लगता है वही हाल भुखेरा जन पार्टी का भी है। अब प्रत्याशी के अपहरण के छल कपट के जवाब में जब कांग्रेस ने नोटा पर बटन दबाने का आहान किया तो यहां भी अपने ही कुकर्मों से भुखेरा जन पार्टी डर गई। यदि ईमानदारी से वोटों की गिनती की जाएगी जो कि कभी नहीं होती और ना होगी। लगभग 5 लाख वोट इंदौर में नोटा में डाले जाएंगे। और यह अधिकतम नोटा में वोट डालने का कांग्रेस का प्रति उत्तर पूरी दुनिया में गूंजेगा।

ECI ने पहले 2 चरणों के मतदान डेटा में देरी की

पेज 8 का शेष

'प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूर्ण संख्या क्यों नहीं बताई जाती? जब तक यह आंकड़ा ज्ञात नहीं होता, तब तक प्रतिशत निरर्थक है,'' येचुरी ने कहा कि इससे मतदाताओं की संख्या में बदलाव की आशंकाएं पैदा होंगी और परिणामों में हेरफेर के बारे में भी चिंताएं बढ़ेंगी।

एक स्वतंत्र पत्रकार और वकील, पूनम अग्रवाल, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में गिने गए वोटों की संख्या और डाले गए वोटों की संख्या में विसंगतियां पाईं, ने कहा कि जहां तक आंकड़ों की बात है तो चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के साथ ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। प्रतिशत में हैं। 'चुनाव आयोग ने 2019 के आंकड़ों को 2014 के आंकड़ों से तुलना करके जारी किया। इसलिए, हमें संख्याओं के साथ-साथ मतदान प्रतिशत में वृद्धि और कमी को दर्शाने वाला उचित संकलित डेटा मिला। तब से, चुनाव आयोग शायद ही कभी विस्तृत डेटा साझा करता है, जैसे कि मतदान किए गए वोट। जब तक हमारे पास यह संख्या नहीं होगी कि ईवीएम पर 40,000 वोट डाले गए हैं और 40,000 वोट गिने गए हैं, हम इसकी सटीकता के बारे में कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? हमें संख्याओं की आवश्यकता है, प्रतिशत की नहीं,'' उन्होंने कहा कि संख्याएं मतदान के दिन ही जारी की जा सकती हैं क्योंकि मतदान बंद होने पर मतदान एजेंटों को फॉर्म 17सी दिया जाएगा।

19 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव के पहले चरण में, तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यब्रत साहू से मीडिया ने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न मतदान परिणामों पर पूछताछ की। थूथुकुडी, जहां 59.96% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया था, अगले दिन 66.88% की वृद्धि देखी गई, जिससे संदेह पैदा हो गया। साहू ने कहा कि यह डेटा आधी रात तक अपडेट नहीं किया जा सका और अगले दिन ही अपडेट किया गया। दूसरे चरण में, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कौल ने कहा कि मतदान में देरी हुई क्योंकि चुनाव अधिकारियों को बड़ी संख्या में बाहर आए मतदाताओं के दस्तावेजों को सत्यापित करने में समय लगा। केरल में 71.27% मतदान हुआ, जो 2019 के 77.84% से कम है।

हजारों करोड़ों का घोटाला नगर निगम इंदौर में नाला टेपिंग, नालियां बिछाने में ही

आयुक्त जिला कलेक्टर संभाग आयुक्त महापौर, पार्षदों, जोनल इंचार्ज सहायक उप यंत्री लेखाकार सभी की हिस्सेदारी सभी जिम्मेदार

निगम की हर शाखा में चारों तरफ सैकडो करोड़ के भ्रष्टाचार का यही हाल

नगर निगम इंदौर में हाल ही में समय माया द्वारा वर्षो लिखने के बाद 1999 से महापौर कैलाश विजयवर्गीय के समय विश्व बैंक से मिले 200 करोड़ रुपए से शुरु होने के बाद प्रोजेक्ट उदय, जेएनआरयूएम से गंगा सफाई अभियान के लिए मिले लगभग 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नाला टेपिंग, नालिया बिछाने बार-बार सडके खोदना कभी 1 फुट कभी 2 फुट कभी 3 फुटके पाइप बिछाने के नाम पर पूरे शहर और प्रदेश देश मे लगभग पूरे देश भर में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ इसमे अंदर इंदौर मे ही 5000 करोड रुपए से ज्यादा का खर्चा किया गया जहां नदियो नालो की सफाई करने के साथ जनता की रहवासी स्थलो के निमित्तटी पानी के उपयोग के बाद दूषित जल को व बरसाती पानी को निकालने की उचित व्यवस्था के नाम पर उल्टे ही प्राकृतिक नदियो के व उनके बहाव क्षेत्र के मिलने वाले नालो की भूमियो पर चुने हुए पार्षदो महापौर के साथ सरकारी प्रशासनिक क्षेत्र के संभाग आयुक्त से लेकर कलेक्टर निगम आयुक्त उपायुक्त सहायक आयुक्त से लेकर मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री कार्यपालन यंत्री से उप यंत्री तक भू कॉलोनी माफिया जो राजनीतिक दलों के नेताओ के साथ मप्र गृह निर्माण मंडल आधिकरण नगर निगम ने मिलकर उनके बहाव क्षेत्र की भूमि पर कब्जे करवा कर बड़ी- बड़ी कॉलोनिया बहुमंजिला इमारतें, बाजार सबके नदी नालो को छोटा कर उसमे मोटी कमाई के लिए सड़क तक अनावश्यक रूप से अतिक्रमण कर बनवा तनवा दी गई है। प्रशासनिक क्षेत्र के जितने भी अधिकारी धन देकर यहां पदस्थ हुए। सबका एक ही उद्देश्य था खाओ पियो लूटो 50% लुटा दो हाथ पोछो और चल दो। बेशक पैसा यहां से लेकर शहरी विकास, वित्त, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय मंत्रालय गंगा नदी स्वच्छता मिशन आदि को यथा योग्य हिस्सा बताकर भोपाल से होता हुआ इंदौर तक आया और सभी जिलो की नगर निगमो पालिकाओ परिषदो तक पहुंचा। फर्जी बिल घोटाला प्रदेश के सभी मंत्रालयो के सभी जिलो मे यथा योग्य हर विभाग मे आवंटन मे 2 से 10% तकवेन के बाद चलकर पैसा ऊपर से नीचे आता है और फिर नीचे से यथा योग्य ऊपर तक पहुंचता है।

शहरीय क्षेत्रो मे गंदे पानी की निकासी और वर्षा के बाढ के जल की कोई ठोस योजना टोपो और कान्टूर मेप के हिसाब से बनाकर नियोजित नही की गई। ताकि एक बार की बिछाई गई सामान्य व बाढ के लिये नालियां भविष्य की आबादी और बढ़ती शहरीय सघनता के विकास को ध्यान मे रख अगले 25 50 साल तक पुनः तोड़ना फोड़ना निर्माण न करना पड़े के हिसाब से नहीं की गई।

इंदौर क्षिप्रा कछार मे जो चंबल कछार की और चंबल यमुना कछार की और यमुना गंगा कछार की नदी होने के कारणगंगा की सफाई के नाम पर ही मात्र सन 2014 के बाद से लगभग 3000 करोड रुपए खर्च करने के बाद मे भी थोड़ी सी बरसात मे ही शहर की सड़के तालाब बन जाती है। और हालात यह है की 20 फुट चौड़ी गलियो से लेकर अधिकांश शहर की सड़को मे भी 3- 3बार पिछले 5 सालो मे अच्छी खासी 50 साल के लिए बनाई गई सीमेंट कंक्रीट की सड़को की खुदाई करके 1 फुट 2 फुट 3 फुट कही 5 फुट ताकि पाइपलाइन बेचकर बार-बार सड़कोंको खोद कर छोड़ा गया और यहा तक पैसा लूटने और भ्रष्टाचार करने के लिए एक सड़क मे दाये व बांये तरफ की दोनो तरफ सड़के खोद महीनो तक खुली रख यातायात बर्बाद कर आने जाने वाले वह रह वासियो को परेशानी खड़ी कर पाइपलाइन बिछाई गई। सड़को पर गड्ढ छोड़ दिए गए और यह हालत न केवल इंदौर के नगरी सीमा मे वरन पूरे प्रदेश के हर जिले शहरी आबादी को लूट कर भ्रष्टाचार करने के लिए किया जाता रहता है इसके पीछे मात्र भ्रष्टाचार ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और उसका सीधा सा उदाहरण यह है कि आखिर तीन से पांच की 15000 रुपए वेतन मे काम करने के लिए आखिर पार्षद चुनाव मे करोड़ो रुपए खर्च क्यो करते है। के पीछे नगर निगमो पालिकाओ परिषदो मे जनधन की लूट के तांडव से मोटी कमाई का ही तो खेल है।

2500 करोड़ ₹ का है घोटाला-राठौर

मतदान के दिन पेश होने की फिराक में था

अभय राठौर

इंदौर : नगर प्रतिनिधि। नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले के मुलजिम अभय राठौर से कल अफसरों ने रटे-रटाए जवाब दिए। बड़े अफसरों ने तीन घंटे उससे पूछताछ की। यही कहता रहा कि मैंने भी घोटाला पकड़ा था और उसी वजह से सुनील गुप्ता ने मुझे फंसा दिया। उसने अफसरों को बताया कि घोटाला 2500 करोड़ रुपए का है। चुनाव का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने पेश होने से पहले पकड़ लिया।

चार दिन के रिमांड पर अभय राठौर से सबसे पहले एडीशनल कमिश्नर अमित सिंह ने पूछताछ की, उसके बाद डीसीपी पंकज पांडे और बाद में टीआई विजयसिंह सिसौदिया ने। पुलिस को उसके कब्जे से फाइलें जब्त करना है। फाइलों का जिक्र किया तो कहने लगा कि सरगना ड्रेनेज प्रभारी सुनील गुप्ता है। उसी ने पूरा खेल रचा था और मुझे बलि का बकरा बना दिया। अफसरों ने वजह पूछी तो नीचे सिर कर लिया। कहने लगा कि मैंने घोटाला नहीं किया है। मुझे तो फंसाया जा रहा है। मैंने इंदौर नगर निगम के ट्रेंचिंग घोटाले को पकड़ा था और इसकी शिकायत भी की थी। इस शिकायत को दबाने के चक्कर में मुझे उलझा दिया। उस घोटाले में कई बड़े अफसर शामिल हैं।

एटा से इंदौर आते राठौर ने कहा है कि घोटाला छोटा-मोटा नहीं, पच्चीस सौ करोड़ रुपए का है। नाला टैपिंग और सीवरेज में हुआ है। मेरे साथ सुनील गुप्ता भी शामिल है। जांच कराई जाए तो सब पता चल जाएगा। खुद ही पेश होने की तैयारी में था।

मुझे हटाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया था: ड्रेनेज शाखा के प्रभारी सुनील गुप्ता ने अभय राठौर के आरोपों को नकारा है। उनका कहना है कि मेरी शिकायत करता रहा है। इंदौर में तीन कमिश्नर आए, मेरी शिकायत की थी, लेकिन किसी ने मुझे दोषी नहीं माना और न हटाया। विभागीय लड़ाई के कारण वो मुझे फंसाने की कोशिश में है। मुझे हटाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा चुका है।

56 इंच की दहाड़ क्यों बदली घबराहट में

पेज 1 का शेष

इस सरासर झूठे दावे और खुली सांप्रदायिक अपील के खिलाफ कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी पार्टियों और हजारों आम नागरिकों के भी चुनाव आयोग से शिकायत करने से लेकर, पुलिस से शिकायत करने तक के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले और दूसरे चरण के मतदान के बीच के दौर में अपने चुनावी भाषणों में इसी को अपना मुख्य राग बनाए रखा है। हां! उन्होंने इतना जरूर किया कि बाद में मुसलमान शब्द का प्रयोग न करने की सावधानी बरतनी शुरू कर दी और उसकी एवज में तुष्टीकरण के लाभार्थी की संज्ञा का सहारा लेना शुरू कर दिया। बाद में चुनाव आयोग के एक अनोखे फैसले में, इन भाषणों पर शिकायतों के सिलसिले में भाजपा अध्यक्ष, जेपी नड्डा को पत्र लिखकर जवाब मांगने के बाद भी, प्रधानमंत्री मोदी ने न अपने झूठ से तौबा की और न सांप्रदायिक दुहाई से।

बहरहाल, इस सब के बावजूद दूसरे चरण के मतदान में, 2019 के मुकाबले पहले चरण की जैसी ही गिरावट ने, खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक दुहाई के इस हथियार के भी भोथरा साबित होने के अपने स्पष्ट संकेत से साहब की घबराहट और बढ़ा दी है। आखिर, एक यही तो हथियार है, जिसका इस्तेमाल करने में उन्हें महारत हासिल है। बहरहाल, जैसा कि अनेक राजनीतिक प्रेक्षकों ने दर्ज भी किया है, दूसरे चरण के बाद से संघ-भाजपा की कार्यनीति में बदलावों का एक और चक्र शुरू हो चुका है। बेशक, ऐसा नहीं है कि अब कांग्रेस के घोषणापत्र के संबंध में, उसके संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांटने के आरोपों का सांप्रदायिक झूठ छोड़ ही दिया गया है। कतई नहीं। यह झूठ बराबर दोहराया जा रहा है, किंतु थोड़े बदलाव के साथ। दूसरे चरण के लिए प्रचार के आखिर तक आते-आते, इस झूठ में एक नया तत्व जोड़कर, इसे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों यानी हिंदुओं से आरक्षण छीनकर, मुसलमानों को देने के षडयंत्र की दिशा में बढ़ाया जा चुका था। दूसरे चरण के बाद से अब विशेष रूप से इसी के सहारे सांप्रदायिक दुहाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल, यह बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं है। इसके साथ एक और तत्व भी जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि संघ-भाजपा की मनुवादी/आरक्षणविरोधी प्रकृति तथा उसके जातिगत जनगणना के खिलाफ होने की विपक्ष की आलोचनाओं के संदर्भ में, अबकी बार चार सौ पार का मोदी का नारा, सामाजिक रूप से वंचितों के बीच उल्टा काम कर रहा है। इस चुनाव में भाजपा के कम-से-कम चार प्रत्याशियों के संविधान बदलने के लिए चार सौ जरूरी होने के अलग-अलग दावों से, कमजोर तबकों की इसकी आशंकाओं को बल मिला है कि चार सौ पार के पीछे मंशा, संविधान को ही बदल देने और आरक्षण को खत्म करने की है। इस जोर पकड़ती धारणा से पीछा छुड़ाने की कोशिश में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ आरक्षण की चोरी के आरोपों का स्वर ही तेज नहीं कर दिया है, वे बार-बार इसका भरोसा दिला रहे हैं कि खुद संविधान को बदलना तो दूर, जिसमें आरक्षण भी शामिल है, वे तो किसी और को बदलने भी नहीं देंगे। अमित शाह ने मोदी की ओर से इसकी मोदी गारंटी देनी शुरू कर दी है। घबराहट इतनी ज्यादा है कि मोदी की सभाओं में चार सौ पार का जिक्र तक गायब हो गया है। इतना ही नहीं, अब तो 'फिर एक बार मोदी सरकार' जैसे सीधे नारों से भी बचा जा रहा है और महाराष्ट्र में हाल की अपनी चुनाव सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी गरीबों की सरकार, दलितों की सरकार, पिछड़ों की सरकार के नारे लगवाते नजर आए! इस बीच विकसित भारत के नारे, पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के दावे और भारत के महाशक्ति बना दिए जाने की शेखियां, सब प्रचार की प्राथमिकताओं में पीछे छूट गए हैं। इस तरह, चुनाव के तीसरे चरण की ओर बढ़ते हुए, मोदी की भाजपा कुल मिलाकर बचाव की मुद्रा अपनाने पर मजबूर होती नजर आ रही है। यह उसके खुली सांप्रदायिक दुहाई का सहारा लेने के बावजूद है। उसके दुर्भाग्य से बचाव की यह मुद्रा भी काम आती नजर नहीं आ रही है।

बेशक, अपनी ओर से कोई कसर न छोड़ते हुए, उसने सीधे आरएसएस को भी प्रत्यक्ष रूप से मैदान में उतरने के लिए तैयार कर लिया है और स्वयं आरएसएस सरसंघचालक ने एक बयान जारी कर, इसका ऐलान किया है कि आरएसएस के खिलाफ यह झूठा प्रचार हो रहा है कि वह आरक्षण के खिलाफ है, आरएसएस हमेशा से संविधान-प्रदत्त आरक्षण के पक्ष में रहा है (जो कि सफेद झूठ है) और रहेगा, जब तक कि आरक्षण की जरूरत रहती है।

लेकिन, ये सफाइयां भी बहुत असर करती नजर नहीं आ रही हैं। दूसरी ओर, मोदी सम्मोहन की धुंध छंटने के साथ बेकारी, महंगाई से लेकर बढ़ती तानाशाही तथा बढ़ते सामाजिक-धार्मिक विद्वेष की सच्चाइयां, आम जनता की नजरों में ज्यादा से ज्यादा चुभ रही हैं और इसे बढ़ते पैमाने पर लोग स्वर भी दे रहे हैं। इन हालात में, तीसरे चरण में संघ-भाजपा की बदली हुई चुनावी कार्यनीति की विफलता सामने आने के बाद, चुनाव के बीचों-बीच संघ-भाजपा की घबराहट क्या रूप लेती है, अभी कल्पना करना मुश्किल है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चालें काम नहीं कर रही हैं। साहेब घबराया हुआ है। यह दिलचस्प समय है। यह खतरनाक समय भी है।

शासकीय संपत्तियों की लूट का निजीकरण का खेल

वनों की भूमियों वनस्पतियों वृक्षों जैविक संपदा को बेच लूटने का षड्यंत्र

देश की सत्ता पर 10 साल से छल कपट वाचालता और इवीएम की जालसाजी और भारतीय प्रचनक सेवा के अधिकारियों की लूट व डकैती की मानसिकता से सत्ता पर भाजपा उर्फ मुखेरा जन पार्टी का कब्जा है। जो सतत मानव निर्मित व प्राकृतिक संपदाओं को मोटी दलाली और वसूली पर निजी क्षेत्र को सौंपने का षड्यंत्र कर रहे हैं इस श्रृंखला में अब प्राकृतिक वनों का काम आ चुका है। वनों की वनस्पतियां सैकड़ों प्रजातियों के वृक्षों जिन पर हजारों प्रकार के पशु पक्षियों कीटों की प्रजातियां फलती फूलती और अपना जीवन चक्र पूरा कर प्रकृति के सुचारू संचालन में सहयोग करती हैं। से लेकर हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां फलों औषधीय वृक्षों जिनकी जड़ों उसकी छालों, तने पत्तियां फल फूल आदि सैकड़ों

आने वाली पीढियों के लिए वर्तमान सत्ताधीश डकैत प्राण वायु भी दूभर कर देंगे

प्रकार की मानवों की बीमारियों में चिकित्सा के काम आते हैं। वृक्षों की लकड़ियां वन भूमि जिसमें अनेकों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नदी नाले जन जंगल जानवर जमीन जल वायु जो अभी सर्वजनि के स्तर पर सरकार के पास होती है सबको निजी करण करके सबको मोटी कमाई के लिए चांडाल पूंजी राक्षसों को सौंपना है जो वनों की ली गई भूमि पर हर प्रकार सेवनों के विकसित करने के नाम परन केवल जमीन बेचेंगे व्यावसायिक उपयोग कर वहां कालोनियां कटवाने फैक्ट्रियां खड़ी करने होटल रिसोर्ट व अन्य प्रकार से व्यावसायिक उपयोग कर मोटी कमाई करेंगे स्वाभिक है आने वाली पीढियों के लिए उन वर्षों से निकलने वाली प्राण वायु तक नगरीय क्षेत्रों में न पहुंचने के कारण अनेकों बीमारियों परेशानियों का कारण बनने के साथ पुरी मानव आबादी को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है मात्र अपने मानवीय लालच में मोटी कमाई करने के लिए आखिर यदि वन विभाग में पौधारोपण विकास आदि में भ्रष्टाचार होता है तो उस भ्रष्टाचार की जड़ में तो वही नेता मंत्री मुख्यमंत्री ही होते हैं नानो करोड़ो रुपए खर्च करके चुनाव जीतकर मोटी कमाई लूट भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में आते हैं। वही तो पदस्थी पदोन्नति जो हर कर्मचारी अधिकारी का मौलिक अधिकार है। करने में हर जगह हर काम में पैसे की मांग करते हैं। आखिर सीमित वेतन वाला कर्मचारी अधिकारी उस मंत्री मुख्यमंत्री की मांग को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो क्या करेगा और उसको आधार बना कर ये हरामखोर सुकरों की फौज सत्ता से हटने से पहले सभी मानव निर्मित व प्राकृतिक शासकीय संपदाओं को अपने आप की जागीर समझकर लूटने खाने और लुटाने का खेल डकैत राक्षस मोदी के आने के बाद भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों के इशारे व निर्देशन पर तेजी से किया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने सुधारने इकट्ठा करके सत्ता से हटते ही पहले औलादों को बसा दिया है और उसके बाद ये भी भागने की तैयारी कर चुके हैं। इसलिए मोटी कमीशन पर अपने ही लोगों को पौधारोपण वृक्षारोपण और विकास की आड़ में वनों को बेचने का षड्यंत्र कर हरामखोर आने वाली भविष्य की लाखों प्रकार की वनस्पतियां जैविक संपदाओं व उनकी पीढ़ियों को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। ***भास्कर में छपा यह समाचार तो यही सिद्ध करता है।***

देखभाल का भी जिम्मा छिना, वन विभाग मॉनिटरिंग करेगा

जंगलों की सुरक्षा और पौधारोपण निजी हाथों में, वनकर्मियों की भूमिका खत्म

श्रीमती उषा दुबे के बेटे

राहुल दुबे की रिपोर्ट (इंदौर)

राज्य सरकार ने वन विभाग का मूल काम ही उससे छीन लिया है। इस साल से पौधारोपण और जंगलों की देखभाल वन विभाग नहीं, बल्कि निजी एजेंसी करेगी। इंदौर वन मंडल की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद पौधारोपण करने टेंडर जारी कर दिए जाएंगे।

पौधे उगाने से लेकर लगाने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तक निजी एजेंसी की रहेगी। पौधे लगाने के बाद से पांच साल तक देखरेख कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली एजेंसी ही करेगी। वहीं वनकर्मियों की बात तो वह केवल मॉनिटरिंग का काम करेंगे। खंडवा वृत्त में तो इसके टेंडर जारी भी हो गए हैं। इंदौर डीएफओ महेंद्र सोलंकी कहना है कि जून में प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

औसतन सात लाख पौधे लगाते हैं हर साल

हर साल वन विभाग द्वारा इंदौर वन मंडल में सात लाख पौधे लगाए जाते हैं। 3800 वर्गमीटर के करीब इंदौर वन मंडल का रकबा है। इसमें महज 700 वर्गमीटर में ही जंगल खड़ा है। बाकी जगह वन भूमि खाली पड़ी है। वनकर्मियों को पौधे लगाने के बजाए सुरक्षा में मदद और मॉनिटरिंग करने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है।

अलग-अलग एजेंसी को देंगे कॉन्ट्रैक्ट: वन अधिकारियों का कहना है कि एक वन मंडल में केवल एक एजेंसी को ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। बल्कि रेंज के हिसाब से टेंडर जारी किए जाएंगे। रेंज द्वारा प्रस्ताव बनाकर वन संरक्षक को दिए जाएंगे कि उनकी रेंज में कितनी वन भूमि पर कितने पौधे लगाए जाना है। इसका सत्यापन करने के बाद रेंज वार टेंडर जारी किए जाएंगे।

पौधारोपण में ही सबसे बड़े भ्रष्टाचार का खेल: वन विभाग में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पौधारोपण और उसके बाद उनकी देखभाल के काम में ही होता है। पौधे लगाने के बाद उसे सुरक्षा देने के लिए तार फेंसिंग, फिर गर्मियों में निंदाई, गुड़ाई और सिंचाई के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। पौधे लगाने के बाद लापरवाही आग लगाने की घटना भी बहुत सामान्य है। चार साल पहले देवगुराड़िया की पहाड़ी में यही हुआ था। पौधे लगाने के बाद आग लग गई थी। हाल ही में चोरल रेंज में भी यही चल रहा है। जहां पौधे लगे वहां आग लग गई।

इंदौर मंडल में कागजी पौधारोपण की जांच अभी चल रही है

इंदौर वन मंडल में कागजी पौधारोपण की जांच अभी चल ही रही है। इसके अलावा चोरल और महू में भी अवैध कटाई, आग की घटना की जांच चल रही है। तीन साल पहले चोरल रेंज में तीन रेंजर पर अवैध कटाई पाए जाने पर रिकवरी निकाली गई थी।

ECI ने पहले 2 चरणों के मतदान डेटा में देरी की: इससे चिंताएँ क्यों बढ़ जाती हैं?

चुनाव आयोग, जिसने अंततः 30 अप्रैल को पहले दो चरणों का मतदान प्रतिशत जारी किया, ने अभी तक दोनों चरणों में पड़े वोटों की संख्या सार्वजनिक नहीं की है।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों के लिए मतदान प्रतिशत प्रकाशित करने में देरी को लेकर कड़ी आलोचना की है। अंतिम मतदान प्रतिशत अंततः ईसीआई द्वारा 30 अप्रैल, मंगलवार को जारी किया गया, चरण 1 के 10 दिन बाद और चरण 2 के मतदान के चार दिन बाद।

हालाँकि, चुनाव आयोग ने अभी तक दोनों चरणों में पड़े वोटों की संख्या सार्वजनिक नहीं की है। इसके अलावा, चुनाव आयोग द्वारा घोषित प्रारंभिक प्रतिशत से 5-6% की वृद्धि हुई है।

चरण 1 में 66.14% मतदान दर्ज किया गया जबकि चरण 2 में 66.7% मतदान हुआ। 19 अप्रैल को, पहला चरण समाप्त होने के बाद, चुनाव आयोग ने कहा कि शाम 7 बजे तक मतदान लगभग 60% था। इसी तरह, 26 अप्रैल को दूसरे चरण के बाद, चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान 60.96% था।

आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए मतदान प्रतिशत को संशोधित करना सामान्य बात है, लेकिन ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन और अंतिम मतदान के आंकड़ों के बीच 2-5 प्रतिशत का अंतर असामान्य नहीं था, लेकिन अंतिम डेटा 24 घंटे के भीतर तैयार हो जाता था और चुनाव आयोग निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदाताओं का विवरण सूचीबद्ध करेगा।

'चुनाव आयोग के मोबाइल एप्लिकेशन में चार दिनों तक मतदान प्रतिशत संशोधित होता रहा। फिर भी अंतिम डेटा 30 अप्रैल तक जारी नहीं किया गया था। जब मतदान जारी किया गया था, तब भी इसे प्रतिशत में दिया गया था। डर इस बात का है कि क्या यह आंकड़ा मतदाताओं की सही संख्या दर्शाता है। चुनाव आयोग को इस अत्यधिक देरी और रिपोर्टिंग प्रारूप में अचानक बदलाव के लिए स्पष्टीकरण देना होगा,' उन्होंने कहा।

ईसीआई ने यह जानकारी भी छोड़ दी है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने मतदाता पंजीकृत हैं, वोट डालने वाले लोगों की सटीक संख्या और मतदाताओं की संख्या का सीट-वार विवरण। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेबसाइट केवल राज्य में पात्र मतदाताओं की कुल संख्या और प्रत्येक बूथ में मतदाताओं की संख्या दिखाती है। हालाँकि, इसे विधानसभा क्षेत्रों या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एकत्रित नहीं किया जाता है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी मतदान डेटा जारी करने में देरी और अंततः इसे प्रकाशित करने के तरीके पर अपनी चिंता व्यक्त की।

(शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com
करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत
साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन (प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें
मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है
मो. 9425125569 / 9479535569
ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958